

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4330

जिसका उत्तर 26 मार्च, 2025 को दिया जाना है।
05चैत्र, 1947 (शक)

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 योजना के तहत प्रगति

4330. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित आवेदनों की राज्यवार और आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) स्वीकृति के वर्ष सहित इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का राज्यवार व्यौरा क्या है;
- (ग) उत्तर योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और सीएफसी की वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (घ) ईएमसी योजना के अंतर्गत बिक्री योग्य/पट्टे पर दिए जाने योग्य भूमि क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए तैयार कारखानों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को देशभरके 16 राज्योंसे 31 आवेदन [21 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और 10 सामान्य सुविधाकेंद्र (सीएफसी)] प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 1986.25 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता सहित 4,127 करोड़ रुपये की परियोजनालागत वालेनौ (9) ईएमसी और एक (1) सीएफसी को देशभरके 7 राज्योंमें अनुमोदित किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल है। ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण एमईआईटीवाई की वेबसाइट, <<https://www.meity.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/modified-electronics-manufacturing-clusters-emc-2-0-scheme>> पर उपलब्ध है।

भारत सरकार स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहन बनाना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्यशृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ाना है। भारत सरकार ने घरेलू क्षमता ओं को बढ़ाने, आयात निर्भरता को कम करने तथा भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ प्राप्त हैं।

इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्तवर्ष 2014-15 में 1,90,366 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तवर्ष 2023-24 में 9,52,000 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें लगभग 17.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर ('सीएजीआर') है। अब हम एक ऐसे चरण में पहुँच गए हैं जहाँ भारत में उपयोग किए जारहे 99.2%

मोबाइलहैंडसेटभारतमेंहीबनाएजातेहैंऔरवित्तवर्ष 2022-23 मेंहममोबाइलनियर्तिकरनेवालेदेशबनगएहैं, जबकि वित्तवर्ष 2014-15 मेंहममोबाइलआयातकरनेवालेदेशथे, जबभारतमें बिकनेवालेसभी मोबाइलफोनकालगभग 74% आयातकियाजाताथा। विवरणअनुबंधमेंदियागयाहै।उद्योगकेअनुमानकेअनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्सक्षेत्रमेंलगभग 25 लाखरोजगार (प्रत्यक्षऔरअप्रत्यक्ष) उत्पन्नहुएहैं।

अनुबंध

वित्तीयवर्ष	उत्पादन	नियर्ति
2014-15	190,366	38,263
2015-16	243,263	39,064
2016-17	317,331	39,980
2017-18	388,306	41,220
2018-19	458,006	61,908
2019-20	533,550	82,929
2020-21	554,461	81,822
2021-22	640,810	116,895
2022-23	822,350	189,934
2023-24	952,000	241,157

राशि: करोड़रुपयेमें